

2015/00056

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 27/2015

अपीलांत

बनाम्

दाना पुत्र सालार जाति  
मुसलमान निवासी सुन्दर  
नगर कोनरा तहसील चौहटन

रेस्पोंडेंट्स

1. पारसमल पुत्र रिखबदास  
जाति ओसवाल निवासी  
चौहटन तहसील चौहटन  
2. राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार, चौहटन



राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 07.07.1992 जो तहसीलदार चौहटन द्वारा ग्राम कोनरा के नामान्तरकरण संख्या 822 पर पारित किया गया।

- उपस्थित:—1. श्री बलवन्तसिंह चौधरी अधिवक्ता अपीलांत की ओर से।  
2. श्री पवन सिंहल अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 01 की ओर से।  
की ओर से।  
3. श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 13.06.2018

1. अपीलांत ने यह अपील कोनरा के नामान्तरकरण संख्या 822 पर तहसीलदार, चौहटन द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.1992 के विरुद्ध धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में अपीलांत की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांत एवं रेस्पोंडेंट संख्या 01 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 643 रकबा 60-04 बीघा मौजा सुन्दर नगर पटवार क्षेत्र कोनरा में आयी हुई थी। अपीलांत एवं रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार चौहटन के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। बंटवाड़ा आदेश दिनांक 16.06.1992 की पालना में पटवारी हल्का कोनरा ने नामान्तरकरण संख्या 822 भरकर तहसीलदार, चौहटन के समक्ष पेश किया। जिस पर तहसीलदार, चौहटन ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.1992 द्वारा स्वीकृत कर दिया। अपीलांत ने इस विभाजन आदेश को बिना विधिवत बंटवाड़ा करवाये गलत बताते हुए इस आधार पर पारित नामान्तरकरण संख्या 822 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। अपीलांत ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांत ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया गया।

जिला कलक्टर  
बाड़मेर

3. हमने अपील, अपीलांट मियाद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को सम्मन किये एवं अपीलाधीन रिकॉर्ड तलब किया।
4. हमने दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 643 रकबा 60-04 बीघा मौजा सुन्दर नगर पटवार क्षेत्र कोनरा में स्थित है जिसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा व रेस्पोंडेंट संख्या 01 का 1/2 हिस्सा है। इसी हिस्से अनुसार पक्षकारान का कब्जा काशत चला आ रहा है। उक्त हिस्से की भूमि पर अपीलांट की ढाणी,टांके,चारवाड़े व कुआ भी बने हुए हैं एवं अपीलांट व रेस्पोंडेंट का अलग अलग कब्जा काशत है तथा अपने हिस्से अनुसार बाहमी तोर पर बंटवाड़ा भी कर रखा है। वादग्रस्त भूमि के कब्जा काशत व गुणवता व सारभूत तथ्यों की अवहेलना एवं राजस्थान काशतकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 के अन्तर्गत बंटवाड़ा नहीं हुआ। उन्होंने तर्क दिया कि बंटवाड़ा आदेश से सम्बन्धित तहसील कार्यालय चौहटन में कोई रिकॉर्ड नहीं है। रेस्पोंडेंट तहसीलदार चौहटन ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पेशिदा तोर से जमीन की गुणवता का धोरे व समतल भूमि को ध्यान में नहीं रखते हुए बंटवाड़ा कर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 822 दिनांक 07.07.1992 गलत पारित किया है, जो गलत एवं विधि विरुद्ध है। मियाद के सम्बन्ध में इनका तर्क है कि अपीलांट को पूर्व में रेस्पोंडेंट द्वारा वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा करवाकर आलोच्य नामान्तरकरण पारित करने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी परन्तु 10 दिन पूर्व रेस्पोंडेंट संख्या 01 अपने साथ अजनबी व्यक्तियों को लेकर मौके पर आया तथा वादग्रस्त भूमि का बेचान हेतु भूमि दिखाने लगा, तब अपीलांट ने भूमि का बिना विधिवत बंटवाड़ा करवाये बेचान नहीं करने की हिदायत देने पर रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने पूर्व में बंटवाड़ा होने एवं नामान्तरकरण पारित करने का कहा, तब नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की और वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अंदर मियाद पेश की है। अधिवक्ता अपीलांट ने आरआरटी 2018(1) पेज 186, आरआरटी 2017(2) पेज 1412, आरआरटी 2013(2) 878, आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरडी 1989 पेज 45 एवं डीएनजे 2015 (SC) 584 के कानूनी दृष्टांत पेश कर अवैध नामान्तरकरण में विलम्ब घातक नहीं होने, सहमति का प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने एवं अनाधिकृत एवं शून्य आदेश को कभी भी चुनौती देने के तर्क प्रस्तुत करते हुए अपील अंदर मियाद सुमार कर नामान्तरकरण संख्या 822 दिनांक 07.07.1992 निरस्त करने का निवेदन किया।
5. इसके जवाब में रेस्पोंडेंट संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाया है, जिसके फलस्वरूप नामान्तरकरण संख्या 822 दिनांक 07.07.1992 पारित किया गया है। इसमें कोई त्रुटि नहीं हुई है। हस्तगत अपील में तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित

जिला कलक्टर  
बाड़मेर

विभाजन आदेश के अनुसरण में पारित नामान्तरकरण को चुनौती दी है। इस नामान्तरकरण अपील में विभाजन आदेश को खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसी दिशा में यह अपील चलने योग्य नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलांत ने वादग्रस्त भूमि का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कलक्टर न्यायालय चौहटन में पेश किया, जो विचाराधीन है, जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। इन तथ्यों को अपीलांत ने अपील में उल्लेख नहीं कर छिपाया गया है। अपीलांत स्वच्छ हाथों को रखे हुए नहीं आया है और मिथ्या कथन किये हैं। इसलिये भी अपील चलने योग्य नहीं है। मियाद के सम्बन्ध में उनका तर्क है कि अपीलांत्स को अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान था अपीलांत ने अपील 23 वर्ष बाद पेश की है, जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। इसलिये अपीलांत की अपील मियाद बाहर होने एवं गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाए।

6. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 822 एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम कोनरा के खेत खसरा नम्बर 643 रकबा 60-04 बीघा भूमि अपीलांत एवं रेस्पोंडेंट संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें अपीलांत का 1/2 हिस्सा व रेस्पोंडेंट संख्या 02 का 1/2 हिस्सा है। अपीलांत का यह कथन है कि अपीलांत व रेस्पोंडेंट संख्या 01 की भूमि का विधिक न्यायिक प्रक्रिया से राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 के अन्तर्गत बंटवाड़ा नहीं हुआ है और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौहटन ने अपीलांत को बिना सुनायी का अवसर दिये पैशिदा तौर से जमीन की गुणवत्ता का धोरे व समतल भूमि का ध्यान नहीं रखते हुए भूमि का विभाजन बताते हुए बंटवाड़ा का नामान्तरकरण संख्या 822 गलत एवं विधि विरुद्ध पारित किया है। जबकि रेस्पोंडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता का यह कथन है कि अपीलांत व रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाया है, जिसके फलस्वरूप नामान्तरकरण संख्या 822 दिनांक 07.07.1992 पारित किया गया है। इसमें कोई त्रुटि नहीं हुई है और वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांत ने सहायक कलक्टर चौहटन के न्यायालय में दावा विचाराधीन होना बताया है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार चौहटन से विभाजन आदेश की मूल पत्रावली तलब करने पर तहसीलदार चौहटन ने अपने पत्रांक राजस्व 2018/586 दिनांक 27.04.2018 द्वारा मौजा कोनरा के खसरा नम्बर 643 रकबा 60'04 बीघा भूमि के विभाजन आदेश दिनांक 16.06.1992 की पत्रावली रेकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होना बताया है। इसके अतिरिक्त पक्षकारान के अधिवक्ता ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच सहायक कलक्टर चौहटन के न्यायालय में वादग्रस्त भूमि का दावा विचाराधीन बताया है और इसी वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पारित नामान्तरकरण संख्या 822 के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 07.07.1992 के विरुद्ध इस न्यायालय में अपीलांत ने अपील पेश कर अनुतोष चाहा है, ऐसी स्थिति में मामले के हालात को देखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि



जब तक सहायक कलक्टर, चौहटन के न्यायालय में विचाराधीन दावा का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक दोनो पक्ष आराजी खसरे की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें और विचाराधीन दावे के निर्णयोपरान्त विधिवत कार्यवाही करें। इसी अनुसार पत्रावली का निस्तारण किया जाता है।



(शिवप्रसाद एम. नकाते)  
जिला कलक्टर बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर